भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा मुख्यालय में शनिवार को कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद थीं।

''बन्ना म्हारो केशरियो हजारी गुल रो फूल...'', मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं का आव्हान किया

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा, भाजपा की सरकार ने सत्ता संभालते हुए एस.आई.टी. गठित की और 7 माह में 115 पेपर माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया

- **नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी ने कहा, केंद्रीय नेतृत्व ने सहज, सरल और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को प्रदेश की कमान सौंपी।**
- **इस अवसर पर वसुंधरा राजे ने कहा, राजनीति में पद, मद और कद महत्वपूर्ण है। जनता के प्यार और विश्वास से अर्जित करें स्थाई कद।**

जयपुर, 3 अगस्त, (का.सं.)। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पदभार ग्रहण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान और स्वाभिमान के लिए खून पसीना एक कर दूंगा। उन्होंने कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति को देखकर भावविभोर होकर कहा कि जो स्नेह और सम्मान मुझे दिया गया है, उसका मैं ऋणी हूं। जो मार्गदर्शन मुझे मिला है, उसके अनुसार संगठन और सत्ता के मध्य सेतु बनकर शीर्ष नेतृत्व द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जिस मोहल्ले में रहते हैं, वो वहां सरकार के प्रतिनिधि हैं। आज राज कार्यकर्ताओं का है, सरकार कार्यकर्ताओं की है और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक ले जाने की जिम्मेदारी भी कार्यकर्ताओं की है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने राजस्थानी गीत का उदाहरण देते हुए कहा, विवाह में दूल्हे के लिए परिजन महिलाएं गीत गाती हैं कि ''बन्ना म्हारो केशरियो हजारी गुल रो फूल...''। वैसे ही देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राजस्थान का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हम सबके दूल्हा हैं। राठौड़ ने कहा कि मेरे पूर्ववर्ती नेतृत्वकर्ताओं ने संगठन को मजबूती देने का और आगे बढ़ाने का काम बड़ी शिद्दत से किया है। मैं उनसे प्रेरणा लेकर और उनके मार्गदर्शन में जो विश्वास केन्द्रीय नेतृत्व ने जताया है और जो भरोसा कार्यकर्ताओं ने किया है, उस पर खरा उतरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का अभिनंदन करते हुए कहा कि मदन राठौड़ के नेतृत्व में हम सब भाजपा के विचार की इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने विचार और संस्कार के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुशासन में जनता परेशान थी, पेपरलीक हो रहे थे। भाजपा की सरकार बनने के साथ ही एस.आई.टी. का गठन कर पेपर माफियाओं की कमर तोडने का काम किया गया। आज 115 से ज्यादा पेपर माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अभी तो मछलियां पकड़ी गई हैं, मगरमच्छ बाहर हैं, मैंने उनको भी कहा है और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्द ही मगरमच्छ भी शिंकजे में होंगे।

भाजपा के निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस जाति और मजहब के नाम पर देश को बांटने का षडयंत्र कर रही है। उसे रोजे में रोजेदारों के लिए अलग से व्यवस्थाएं करना अच्छा लगता है लेकिन श्रावण के पवित्र माह में कावडियों की आस्था का सम्मान करना नागवार गुजरता है।

उन्होंने कहा, केन्द्रीय नेतृत्व ने मदन राठौड जैसे सहज, सरल और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को प्रदेश की कमान सौंपी है। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार, और हम सब मिलकर उनके नेतृत्व में काम करेंगे।

भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस अवसर पर कहा कि राजनीति में उतार-चढाव आते रहते हैं, हर किसी को इस दौर से गुजरना पड़ता है। राजनीति में तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं, पद, मद और कद। पद और मद तो आते जाते हैं लेकिन, जो व्यक्ति अपने काम से कद को बना लेता हैं, यही उसकी पूंजी है। जनता के प्यार और विश्वास से अर्जित कद स्थाई है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल पार्टी नहीं है, एक परिवार है और इस परिवार की सदस्य होकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूं।

भाजपा प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने कहा कि वसुंधरा जी की पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान की हमारी भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार, हमारे लिए लोक कल्याण सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, हम सबका पूरा विश्वास है कि अपने अनुभव से संगठन की ऊर्जा का उपयोग करते हुए मदन राठौड भाजपा को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे।

इस अवसर पर मंच संचालन भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र गोठवाल ने किया और प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने आभार व्यक्त किया। मंच पर राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, सतीश पूनिया व अरुण चतुर्वेदी सहित अनेक वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की।

कार्यक्रम में संत शक्ति का मिला आशीर्वाद

कार्यक्रम में अलग से बने एक मंच पर प्रदेश के प्रख्यात साधु-संत उपस्थित थे। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड को संतजनों ने अपना आशीर्वाद दिया। वे मंच पर पहुंचते ही सबसे पहले संत शक्ति के मंच पर पहुंचे और आशीर्वाद लिया।

जयपुर एयरपोर्ट से प्रदेश मुख्यालय तक जोरदार स्वागत

भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड के राजधानी दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने भाव-भीना स्वागत किया। इसके बाद युवा मोर्चा के नेतृत्व में बाइक रैली एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक निकालकर नए प्रदेश अध्यक्ष की अगवानी की गई। इस दौरान रास्ते में भाजपा के विभिन्न मोर्चा, प्रकोष्ठों और सामाजिक संगठनों की ओर से पुष्पवर्षा एवं ढोल-नगाड़ों के साथ नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया।

विधि विधान पूर्वक संभाली जिम्मेदारी

भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचने पर वैदिक पूजा अर्चना के बाद नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड ने निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से प्रदेश के नए अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, संगठन सह प्रभारी विजया राहटकर, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल, पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, भाजपा कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक सहित प्रमुखजन उपस्थित थे।

प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में चार संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को मंजूरी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया

- **इन उपक्रमों से 1 लाख 34 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा।**
- **इन संयुक्त उपक्रमों से प्रदेश में मेट्रो परियोजनाओं को गति मिलेगी।**

जयपुर, 3 अगस्त (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में ऊर्जा क्षेत्र में चार संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को मंजूरी दी गई। इन उपक्रमों से प्रदेश में 1 लाख 34 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। इसके अलावा जॉइंट वैंचर (जे.वी.) कंपनी से प्रदेश में मेट्रो परियोजनाओं का संचालन होगा। वहीं संस्कृत शिक्षा विभाग में पदनाम परिवर्तन, इसी के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग में सुपर स्पैशिएलिटी शिक्षकों की कमी दूर करने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार और राज्य के बीच संयुक्त उद्यम (जे.वी.) कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान में चल रही एवं भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास, परिचालन एवं क्रियान्वयन के लिए होगा। मेट्रो रेल नीति-2017 के अनुसार इस जे.वी. को भारत सरकार से मेट्रो परियोजना लागत में वित्तीय सहयोग (अंशपूंजी एवं ऋण के रूप में) प्राप्त हो सकेगा। साथ ही, राज्य की मेट्रो परियोजनाओं के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

मंत्री ने बताया कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गत 10 मार्च को राज्य सरकार और विभिन्न केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर यूनिट (पी.एस.यू.) के बीच हुए एम.ओ.यू. की अनुपालना में मंत्रिमंडल की बैठक में भारत सरकार की विभिन्न पी.एस.यू. के साथ जॉइंट वैंचर कंपनियों के गठन के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। इन परियोजनाओं में राज्य सरकार की कंपनियों की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत और केन्द्रीय पी.एस.यू. कंपनियों की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत रहेगी।

उन्होंने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आर.वी.यू.एन.एल.) के बीच दो अलग अलग जॉइंट वैंचर की स्थापना की जाएगी। इसमें एक तापीय परियोजना एवं दूसरी अक्षय ऊर्जा परियोजना होगी। इन जेवी से बिजली की बेस लोड और पीक लोड डिमांड पूरी होगी। साथ ही बिजली उत्पादन में प्रदेश के वित्तीय भार में कमी आएगी। पहली परियोजना के अंतर्गत कालीसिंध तापीय परियोजना झालावाड़ परिसर में 800 मेगावाट की इकाई या किसी अन्य पीटहैड ग्रीनफील्ड कोयला परियोजना की स्थापना की जाएगी। दूसरी जेवी के तहत दो हजार से ढाई हजार मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना, पंप स्टोरेज परियोजना और पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी। इन परियोजनाओं से 17 हजार 200 करोड़ से 24 हजार 400 करोड़ रूपये का प्रदेश में निवेश होगा।

मंत्री ने बताया कि अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए एन.टी.पी.सी. ग्रीन एनर्जी एवं आर.वी.यू.एन.एल. के मध्य जॉइंट वैंचर होगा। यह उपक्रम 25 हजार मेगावाट की सोलर/विंड/हाइब्रिड एनर्जी सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करेगा। इसके माध्यम से प्रदेश में एक लाख करोड़ रूपये का निवेश होगा।

उन्होंने बताया कि विद्युत प्रसारण परियोजनाओं की स्थापना के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के मध्य जॉइंट वैंचर कंपनी की स्थापना की जाएगी। इससे राजस्थान में बढ़ती विद्युत लोड की मांग की पूर्ति के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली का विकास हो सकेगा। यह जे.वी. (निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं रखरखाव) आधार पर ट्रांसमिशन सिस्टम का संचालन करेगी और अपने द्वारा बनाई गई संपूर्ण ट्रांसमिशन क्षमता राजस्थान डिस्कॉम को उपलब्ध करवाएगी। इस जे.वी. के माध्यम से प्रदेश में 10 हजार करोड़ का निवेश होगा।

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2024-25 के लेखानुदान में प्रसारण निगम में केन्द्र सरकार के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) लाने की घोषणा की गई है। इसकी अनुपालना में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड इनविट का गठन करेगा तथा इसे सेबी में पंजीकृत किया जाएगा। आर.वी.पी.एन. को इनविट के माध्यम से अपनी परिचालन ट्रांसमिशन परिसंपति के मुद्रीकरण के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव आज अनुमोदित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वर्गीकृत कर दें तथा यह कारण बता दें कि उन लोगों के पास तो नौकरी हैं। लेकिन यह एक अन्याय होगा क्योंकि स्वीपर का काम करने वाली जातियों के साथ बहुत अधिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक भेदभाव होता आ रहा है। संविधान-निर्माताओं ने, एस.सी./एस.टी. के सजातीय वर्गों के प्रति ''ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक भेदभाव के आधार पर, उनको आरक्षण दिया था। इस विचार की दलील है कि आरक्षित कोटा के अन्दर उपश्रेणी बना देने से संविधान की भावना ही पीछे छूट जायेगी। चिराग पासवान ने कहा ''एस.सी./एस.टी. कोटा में क्रीमी लेयर निर्धारित करने की अनुमति हरगिज़ नहीं दी जा सकती। एस.सी./एस.टी. कोटा के अन्दर उपश्रेणियाँ बनाने से उस सामाजिक रूप से उपेक्षित तबके के उत्थान का उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा, जो छुआछूत का शिकार रहा है।

यह भी सम्भव है कि शीर्ष अदालत का यह निर्णय दलित राजनैतिक के नए ब्रान्ड के उभरने का कारण बन जाये, क्योंकि दलित और आदिवासी वर्गों के विभिन्न श्रेणियों या उप-श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता तथा राजनैतिक दल उभर कर आ सकते हैं।

इसके साथ ही, राष्ट्रीय जातिगत जनगणना की माँग भी सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद जोर पकड़ सकती है क्योंकि राज्य सरकारों को उन जातियों की उप-श्रेणियों के सामाजिक-आर्थिक पैटर्न से सम्बन्धित आँकड़ों की जरूरत पड़ेगी।

पश्चिमी देशों में भारतीय मूल के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नीतियों, खासकर आतंक समन्वय को रोकने में इन्टरनेट सेवाओं को निलम्बित करने को लेकर की गई उनकी आलोचना ने भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाया।

भारतीय मूल की होने और भारत के साथ पारिवारिक रिश्ते होने के बावजूद जयपाल ने अमेरिकी कांग्रेस में भारत के खिलाफ एक भ्रामक प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्देश्य प्रकट रूप से अमेरिका की सरकार को प्रभावित करना था, लेकिन विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस मामले में एक सटीक फटकार लगाई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ऐसी राजनीतिक शोशेबाजी के बावजूद भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की सामर्थ्य है।

निक्की हैली, प्रीत भरारा, बॉबी जिन्दल और सुएला ब्रेवरमैन जैसे भारतीय मूल के अन्य राजनेता ऐसी ही मनोवृत्तियों का प्रदर्शन करते हैं। अग्रणी रिपब्लिकन एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ में अमेरिका की पूर्व राजदूत रह चुकीं हेली ने प्राय: ऐसा स्टैण्ड लिया, जो उनकी पार्टी की नीतियों से तो मेल खाता था किन्तु भारतीय हितों के विपरीत था। इस बात का एक उदाहरण यह है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर हुई चर्चा में उन्होंने भारत और चीन को ''दो प्रदूषक'' देश बताया था। यह भाषण अमेरिका में तो राजनीतिक दृष्टिकोण से लाभप्रद है किन्तु भारत की विकासात्मक चुनौतियों और ऊर्जा के सतत प्रयासों की अनदेखी करता है।

अमेरिका के दक्षिणी जिले में यू.एस.अटॉर्नी रह चुकी प्रीत भरारा ने भारतीय कूटनीतिक देवयानी खोब्रागडे के कथित वीज़ा घोटाले के लिए हुए अभियोजन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी कूटनीतिक जंग भी चली। खोब्रागड़े को अपने कपड़ों की तलाशी न लिए जाने की कूटनीतिक छूट प्राप्त थी, लेकिन इस मामले में भरारा का कहना था कि यह एक नियमित प्रक्रिया है, और इससे भारतीय नाराज़ हो गए थे। भरारा का रुख प्राय: इन धारणाओं को जन्म देता है कि वह अपनी खुद की नस्ल के लोगों को ही निशाना बनाती हैं।

यू.के. की पूर्व गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन को अपने ''प्रवासी-रोधी'' रुख के लिए जाना जाता था। उन्होंने प्रवासन को आंधी-तूफान की संज्ञा दी थी। विडम्बना यह है कि ब्रेवरमैन के स्वयं के माता-पिता ने 1960 के दशक में यू.के. में भारत के साथ एक व्यापार समझौते की यह कहकर आलोचना की थी कि भारतीय अपनी वीज़ा अवधि खत्म होने के बावजूद यू.के. में जमे रहते हैं।

अमेरिकी इतिहास में पहले भारतीय-अमेरिकी गवर्नर बने बॉबी जिन्दल ने स्वयं को भारतीय वंशक्रम से हटाकर ईसाई धर्म ग्रहण कर अपनी अमेरिकी पहचान स्थापित की। इससे उन्हें रिपब्लिकन राजनीति में आगे बढ़ने में मदद मिली।

लेकिन इन दबावों के बावजूद भारतीय मूल के सभी नेताओं ने अपनी जड़ों को पूर्णतया नहीं त्यागा है, यद्यपि विदेशों में उनके राजनीतिक अभ्युदय की परिणति भारत के लिए वास्तविक लाभों में नहीं होती। उदाहरण के लिए यू.के. के प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक के कार्यकाल में, उनके भारतीय मूल और हिन्दू पहचान के बावजूद भारत-यू.के. व्यापार समझौते में थोड़ी-बहुत प्रगति हुई।

2023 में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के आरम्भ में एक अग्रणी ग्लोबल इन्वैस्टमैंट माइग्रेशन एडवायज़री फर्म ने खुलासा किया था कि गत तीन वर्षों में 17,000 से ज्यादा करोड़पतियों, जिनमें प्रत्येक की नैटवर्थ एक मिलियन डॉलर से अधिक थी, ने भारत छोड़ दिया है। उच्च नैटवर्थ और कुशल भारतीयों के भारत छोड़ने का कारण अपारदर्शी कर नीतियों और मनमाने का प्रशासन का परिणाम हो सकता है, इसके अलावा गत एक दशक से भारत में भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि ये लोग सिंगापुर, यू.ए.ई., यू.के. और अन्य जगहों को पसंद कर रहे हैं। यह एक ऐसी आर्थिक स्थिति जो हमारे राजस्व के आधार को भारी नुकसान पहुंचाएगा।

कांग्रेस ने भाजपा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम मतदान आंकड़े जारी करने में चुनाव आयोग को इतना अधिक समय क्यों लगा, जबकि तकनीकी आधुनिक तकनीकी प्रक्रिया हर दो घंटे में आंकड़े अपडेट होते हैं। उन्होंने कहा, पहले चरण के मतदान के लिए फाइनल आंकड़े जारी करने में चुनाव आयोग को ग्यारह दिन लग गए, दूसरे चरण के लिए उसने 6 दिन लिए तथा बाद के चरणों के लिए 4 से 5 दिन।

दीक्षित ने कहा, इससे ना केवल भारतीय चुनाव आयोग, की विश्वसनीयता परा सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि समस्त चुनाव प्रक्रिया को लेकर संदेह पैदा हो गया है। दीक्षित चुनाव आयोग के इस स्पष्टीकरण से सहमत नहीं थे कि मतदान के फाइनल आंकड़े देर से जारी करने के पीछे संचार व इन्टरनैट मुख्य कारण थे। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट टैक्नोलॉजी की उपलब्धता के कारण प्रारंभिक तथा अंतिम आंकड़ों में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सन् 2019 में, प्रारंभिक तथा अंतिम मतदान आंकड़ों में करीब एक प्रतिशत का अंतर था और पांच सालों के बाद औसत अंतर बढ़कर 4.7 प्रतिशत हो गया है। दीक्षित ने कहा, अगर चुनाव आयोग संतोषजनक जवाब नहीं दे सका तो कांग्रेस इस मामले में जाँच के लिए उच्चस्तर पर संपर्क करेगी।

21 साल से कम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वित्त सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड और राजकोष निदेशक के साथ राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश संदीप व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 20 जून, 2023 को कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसमें अभ्यर्थी की उम्र न्यूनतम 21 साल रखी गई थी। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के अलावा अन्य अभ्यर्थी के भर्ती की लिखित परीक्षा में कम से कम चालीस फीसदी अंक होने चाहिए थे।

याचिका में कहा गया कि भर्ती विज्ञापन की इन दोनों शर्तो की अवहेलना हुई है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया है, जिनके पास भर्ती की लिखित परीक्षा में चालीस फीसदी अंक नहीं हैं। इसके साथ ही कई अभ्यर्थियों को 21 साल की उम्र पूरी नहीं होने के बावजूद चुन लिया गया है, जिसके चलते दूसरे पात्र अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए भर्ती विज्ञापन की इन दोनों शर्त पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है।

महाराष्ट्र के चुनाव की गहमा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ए.एन.आई. की खबर के अनुसार, शाह ने कहा था कि ''महा विकास अघाड़ी गठबंधन औरंगजेब फैन क्लब है। यह औरंगजेब फैन क्लब भारत की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता है। उद्धव ठाकरे इस औरंगजेब फैन क्लब के मुखिया हैं। यह फैन क्लब महाराष्ट्र व भारत की सुरक्षा नहीं कर सकता है। यह तो सिर्फ भाजपा ही है जो सबकी सुरक्षा व रक्षा कर सकती है।''

शाह ने यह भी आरोप लगाया कि ''उद्धव ठाकरे ने कसाब के साथ संलप्ति लोगों के साथ बैठकर खाना खाया था और वो पी.एफ.आई. का समर्थन करते हैं और ठाकरे, औरंगाबाद का नाम बदलकर ''संभाजी नगर'' रखने वालों के खिलाफ हैं।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब शाह ने शिव सेना (यू.बी.टी.) के अध्यक्ष पर सार्वजनिक रुप से हमला बोला है। उन्होंने ठाकरे पर लोकसभा चुनावों के दौरान भी सत्ता के लिए अपनी विचारधारा छोड़ने का आरोप लगाया था।

उद्धव ठाकरे को जून 2022 उस समय मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिव सेना में बगावत हुई थी। इसके फलस्वरुप, उनकी सरकार गिर गई थी। फरवरी 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को असली शिव सेना के रुप में मान्यता प्रदान की थी। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव इस वर्ष के आखिर में होने की संभावना है।

'मृत कर्मचारियों ....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जितेन्द्र के पिता करौली जिले की स्कूल में प्रबोधक पद पर तैनात थे।

इस दौरान नवंबर, 2014 में उनकी मौत हो गई। इस पर याचिकाकर्ता की मां ने अपनी अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन काफी दिनों तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके लिए विभाग के उच्चाधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा, लेकिन तय समय पर उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई।

वहीं, याचिकाकर्ता के वयस्क होने पर विभागीय अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की मां के आवेदन को निरस्त कर याचिकाकर्ता से आवेदन ले लिया। इसके बाद उसे नियुक्ति देने की कार्रवाई भी शुरू कर समस्त औपचारिकताएं पूरी कर लीं, लेकिन उसे नियुक्ति नहीं दी। वहीं, 5 फरवरी 2024 को उसका अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कर्मचारी की मौत के इतने सालों बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।

इसी प्रकार दूसरे याचिकाकर्ता राहुल गुप्ता का आवेदन भी देरी के आधार पर खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के पिता वरिष्ठ लिपिक के पद पर करौली जिले में कार्यरत थे। उनका जून 2018 में असामयिक निधन हो गया था। उनके स्थान पर याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन 24 नवंबर 2023 को इसका आवेदन भी देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

हिमाचल में 47 लापता लोगों का अब तक सुराग नहीं मिला

शिमला, 03 अगस्त। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की तीन घटनाओं में लापता हुए 47 लोगों का अभी भी पता नहीं चला है, इन सभी की तलाश की जा रही है। बुधवार रात को मंडी, शिमला व कुल्लू में बादल फटने की घटनाओं से भारी तबाही हुई है। शिमला के समेज में 33 लोग लापता हैं जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसके अलावा कुल्लू में नौ और मंडी में पांच लोग लापता हैं। अभी तक छ: लोगों के शव बरामद किए गए हैं। जिनमें पांच मंडी के और एक कुल्लू का है। फिलहाल सेना, एन.डी.आर.एफ. और स्थानीय प्रशासन के 400 लोग तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं।

'कोचिंग इन्स्टिट्यूट्स ....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कांग्रेस महासचिव सूचना-प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि आंकड़े राज्यसभा को उपलब्ध कराए गए हैं उनसे पता चलता है कि वर्ष 2019 से 2024 के द्वारा कोचिंग संस्थानों से प्राप्त जी.एस.टी. की राशि में तीव्र गति से वृद्धि हुई है और यह राशि 2,241 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,517 करोड़ पहुंच गई है।

कांग्रेस की इस मांग को बढ़ते हुए कोचिंग उद्योग के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है जिसे टाला नहीं जा सकता है क्योंकि यह आवश्यकता आधारित मांग है, अत: इसके समाधान की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि इन संस्थानों से जी.एस.टी. के संग्रहण में 146 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि हुई है, इसके कुछ हिस्से का उपयोग इसे अच्छे तरीके से लागू करने में लगाया जाना चाहिए परन्तु इसका हिस्सा उभरते हुए इसके बाजार के आकार में होना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि बेशुमार बढ़ते हुए कोचिंग संस्थानों की समस्या से निपटने के लिए भारत में एक समग्र समाधान नीति लाने की जरूरत है। पाठ्यक्रम को भी संशोधित किए जाने की आवश्यकता है और इसे स्कूलों की अन्य गतिविधियों के साथ लाना चाहिए, सभी परीक्षा-आयोजकों को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है इसके साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए और अधिक निवेश किए जाने की जरूरत है।

झारखंड सरकार महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए देगी

रांची, 03 अगस्त। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा (जे.एम.एम.) सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 21 से 50 साल की महिलाओं को हर साल 12 हजार रुपये देगी। इस योजना को मईया सम्मान योजना नाम दिया गया है। झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। माना जा रहा है कि महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन सरकार यह योजना लेकर आई है।

झारखंड सरकार ने इस योजना के ऐलान के साथ ही इसे अमल में लाने के लिए जोरशोर से काम शुरू कर दिया है। राज्य का महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग पात्र महिलाओं को इससे जोड़ने के लिए शिविरों का आयोजन कर रहा है। राज्य के सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को इस योजना को सफल बनाने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं।

झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टैक्नॉलजी ने इस योजना का पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल के जरिए ही आवेदनों का सत्यापन होगा। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार का दावा है कि पोर्टल पर एक घंटे में ही 36 हजार हिट हुए और एक दिन में करीब 15 लाख हिट हो गए। उन्होंने भरोसा जताया कि मईया योजना राज्य की महिलाओं के उत्थान में कारगर साबित होगी।

वित्तीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बाद ट्रम्प ने दावा किया कि आज के विपरीत उन्होंने अमेरिकन बंदियों को जल्दी छुड़वाया था और रुस को कोई छूट नहीं दी गई थी। लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि तब भी रुस के बंदियों की रिहाई का सौदा हुआ था। अमेरिकन मध्यस्थों ने एक फाइनैंशियल अखबार ''वॉलस्ट्रीट जर्नल'' के पत्रकार की रिहाई सुनिश्चित करवाई थी। वर्तमान सौदे में अमेरिकन नेवी के कर्मियों की रिहाई करवाने की बात भी चल रही है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908